



Anil Kumar Maurya &lt;anilkumarmaurya9125142451@gmail.com&gt;

**Non-Compliance and Correction of District Name in Case No. S-08/A/0554/2025**

1 message

Anil Kumar Maurya &lt;anilkumarmaurya9125142451@gmail.com&gt;

29 November 2025 at 15:50

To: teh-sadar.mi@up.gov.in

Cc: hearingcourts8.upic@up.gov.in, sdm-sadar.mi@up.gov.in

To: [teh-sadar.mi@up.gov.in](mailto:teh-sadar.mi@up.gov.in) CC: [hearingcourts8.upic@up.gov.in](mailto:hearingcourts8.upic@up.gov.in), [sdm-sadar.mi@up.gov.in](mailto:sdm-sadar.mi@up.gov.in), [anilkumarmaurya9125142451@gmail.com](mailto:anilkumarmaurya9125142451@gmail.com) From: Anil Kumar Maurya [anilkumarmaurya9125142451@gmail.com](mailto:anilkumarmaurya9125142451@gmail.com) Subject: URGENT: Non-Compliance and Correction of District Name in Case No. S-08/A/0554/2025 | Anil Kumar Maurya vs. Tehsildar, Mirzapur Sadar

Dear Shri Vishal Kumar Sharma, Public Information Officer, Office of the Tehsildar, Mirzapur Sadar.

This communication refers to the Second Appeal filed by me (Appellant: Anil Kumar Maurya) before the Honourable State Information Commission, Court S-08, regarding the persistent denial of information under the RTI Act, 2005.

**Case Registration Number:** A-20250102076 **Case File Number:** S-08/A/0554/2025

I am writing to respectfully draw your immediate attention to two critical issues recorded by the Commission and detailed in my submission dated 10/09/2025:

### 1. Typographical Error and Official Address

The official orders issued by the Commission (dated 27.06.2025 and 17.10.2025) have erroneously mentioned the district as **Shahjahanpur** instead of the correct district, **Mirzapur**. This error has been formally noted by me in my submission and requires immediate internal correction by your office to avoid procedural confusion. The correct administrative unit is **Tehsil-Mirzapur Sadar, District-Mirzapur**.

### 2. Mandatory Compliance with Commission's Order

Despite the Commission's explicit directive in its previous order (27.06.2025) and the subsequent final opportunity granted in the latest order dated **17.10.2025**, the requested point-wise information has still not been provided to me.

The order dated 17.10.2025 strictly directs the Public Information Officer to:

a) **Immediately provide** the certified, point-wise information to the appellant (Anil Kumar Maurya) at his known address via registered post. b) **Personally appear** before the Commission on the next hearing date, **06.01.2026**, along with a copy of the information, proof of dispatch, and a written explanation for the delay in compliance.

Your failure to comply with this order is a direct violation of the RTI Act and the authority of the Commission, which has already indicated that **punitive proceedings**

**under Section 20(1)** of the Act may be initiated against the PIO for continued non-compliance.

I request you to ensure immediate compliance with the Commission's directive and provide the five points of requested information (as listed in my submission dated 10/09/2025) without any further delay, well in advance of the next scheduled hearing.

Sincerely,

Anil Kumar Maurya Appellant Mobile No: 9125142451



tehsadmzp.pdf  
659K

श्री अनिल कुमार मौर्य बनाम ज0सू0अ0 कार्या0 तहसीलदार, तह0-मिर्जापुर, शाहजहांपुर।  
समक्ष- श्री राजेन्द्र सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त, उ0प्र0।

आदेश

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। उभयपक्ष अनुपस्थित है।

प्रश्नगत प्रकरण में आयोग के पूर्व आदेश दिनांक 27.06.2025 को विपक्षी जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि अपीलार्थी को उनके आवेदन पत्र के कम में बिन्दुवार सूचनाएं अगले 15 दिन में उनके आवेदन में दिये गये पते पर पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अगली सुनवाई तिथि पर सूचना की प्रति एवं प्रेषण का साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है और प्रकरण में सुनवाई हेतु आज दिनांक 17.10.2025 की तिथि नियत की गई।

आयोग द्वारा आज की सुनवाई हेतु जनसूचना अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से नोटिस प्रेषित की जा चुकी है। नोटिस प्रेषित किये जाने के बावजूद जनसूचना अधिकारी न तो उपस्थित है और न ही उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी जानबूझकर सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उनका यह रवैया सूचना का अधिकार अधिनियम की उद्देशिका के विपरीत है।

उक्त स्थिति में विपक्षी जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार, तह0-मिर्जापुर, शाहजहांपुर को अंतिम अवसर देते हुये इस निर्देश के साथ नोटिस निर्गत की जाए कि अपीलार्थी को उनके आवेदन पत्र के कम में बिन्दुवार प्रमाणित सूचनाएं अगले 15 दिन में उनके आवेदन में दिये गये पते पर पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा अगली सुनवाई तिथि पर सूचना की प्रति एवं प्रेषण का साक्ष्य तथा सूचना उपलब्ध कराये जाने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपने लिखित स्पष्टीकरण सहित आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है।

वाद वास्ते सुनवाई दिनांक 06.01.2026 को पेश हो।



(राजेन्द्र सिंह)  
राज्य सूचना आयुक्त  
17.10.2025

अपीलार्थी.....

विपक्षी.....